ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **09 April, 2025**

Dr Abhishek Manu Singhvi, MP and Chairman, Law, Human Rights and RTI department, AICC, addressed the media in Ahmedabad, Gujarat, today.

डॉ० अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा- आप लोग ज्यादातर तो हमारे पुराने साथी हैं दिल्ली से और गुजरात से। तो दोस्तों, आप लोगों ने सब सुना है अधिवेशन, आप लोगों को कल का भी कुछ हद तक प्रसंग बताया गया है। मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

पहली बात - यह स्थान, यह दिवस, यह संदर्भ, यह विरासत बार-बार अनेक बिंदुओं से जुड़ी है महान नामों के साथ, महान आत्माओं के साथ और कांग्रेस के साथ। इसलिए माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने सही रूप से इसको कहा कि यह तीर्थ स्थान है। 100 वर्ष गांधी जी की अध्यक्षता के, 150 वर्ष वाली वर्षगांठ सरदार की, तीन हमारे कांग्रेस अध्यक्षों का एक बहुत अंतरंग रिश्ता गुजरात से- दादा भाई नौरोजी से लेकर गांधी और पटेल। नींव कांग्रेस की 25 वर्ष अध्यक्ष रहकर जो सरदार पटेल ने रखी और जो यात्राएं, जो अभियान, जो नाम चिर-परिचित हैं जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई... बारडोली से लेकर दांडी इत्यादि।

बिंदु जो टच हुए, वे व्यापक थे और सबका उद्देश्य एक था कि कांग्रेस के पुनर्निर्माण में यह आवश्यक है कि हम सब हमारी पुरानी विरासत, हमारी पुरानी सोच और हमारी शुरुआत को याद रखें। रेजॉल्यूशन जो सचिन पायलट जी ने मूव किया... अभी मैं आया हूं... तब तक लगभग 25 लोग बोल चुके हैं, राहुल जी बोलेंगे कुछ समय बाद, उसके बाद एक और आपके लिए प्रेस ब्रीफिंग होगी।

बिंदु महत्वपूर्ण हैं कि संविधान के जो स्तंभ हैं, उनको कमजोर कैसे किया जा रहा है। संविधान के स्तंभों में फेडरलिज्म जो है - संघवाद, संघीय ढांचा... उसकी किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने ही वह केस किया

जिसका निर्णय आया कल, जिसमें उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप देना पड़ा कि कोई भी राज्यपाल... इस केस में तमिलनाडु के एक-डेढ़ वर्ष तक बिल्स को पारित नहीं करते और जब दूसरी बार राज्य सरकार भेजती है, तो उसको माननीय राष्ट्रपति को भेज देते हैं। सबको रद्द किया है, सबको निरस्त किया है, बहुत व्यापक और बहुत पुरजोर निर्णय है, वह पढ़ने लायक है। लेकिन कितने निर्णय हों, कितनी बाबासाहेब की घोषणाएं हों, कितने हमारे डॉक्यूमेंट्स हों... यह मोदी सरकार उन सबके उल्लंघन के लिए तत्पर है। इसलिए निर्णय आता है बाद में, उल्लंघन पहले हो जाता है।

संसद की बात की - किस प्रकार से अगर लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कि गणतांत्रिक आवाज है, उसका नाम है सूची में, उसको बोलना है, लेकिन उसको बोलने नहीं दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री इतने प्रखर, इतने मुखर वक्ता हैं, लेकिन दो वर्ष से संसद के अंदर और संसद के बाहर मणिपुर पर एक ऐसी अजीबोगरीब चुप्पी साध चुके हैं कि एक शब्द, एक लाइन नहीं बोले हैं। 26 प्रतिशत टेरिफ के मुद्दे पर विश्व और देश त्राहि-त्राहि कर रहा है। 14 से 20 लाख करोड़ का हनन सिर्फ भारत का फिगर है। 14 लाख मानिए या... 20 लाख करोड़ मानिए फर्क नहीं पड़ता है, विश्व में इससे कई गुना ज्यादा है। संसद में इसकी बात करने से ज्यादा, उसको फास्ट ट्रैक करके उसी दिन और हमने कहा है, हमने आरोप लगाया - जानबूझकर वक्फ का बिल लाया गया। वो डिस्कशन संसद में नहीं होने दिया। संसदीय प्रणाली के प्रति कोई आदर नहीं है।

हर प्रकार से चुनाव आयोग के... और मैं खुद 'ईगल' ग्रुप का सौभाग्यपूर्ण मेंबर हूं, हमारे सब कलीग्स वहां हैं, दिन-प्रतिदिन हर चुनाव में चुनाव आयोग के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगता है... वह बढ़ता ही जाता है, बड़ा ही होता जाता है। लाखों वोटों का फर्क महाराष्ट्र में, डुप्लीकेट वोटर लिस्ट पर... हमने इनके साथ और कई प्रश्न उठाए, उनके जवाब नहीं आते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हम उठाएंगे, हर प्रश्न पर हम अभियान करेंगे। हमने कहा है कि हमारा अंततोगत्वा उद्देश्य है कि कागजी बैलेट हो, लेकिन हम समझते हैं कि कागजी बैलेट तुरंत एक बटन प्रेस करने से नहीं हो सकता, तब तक कम से कम वीवीपैट का जो कागज है... उसका ट्रेल न्यूनतम 50 प्रतिशत हो।

सामाजिक कल्याण की इतनी सारी स्कीम्स हैं, उनका औचित्य क्या है - उनका औचित्य है कि आपको मिले, आपको मिले, आपको मिले। अगर आप इस गैदरिंग में एक नंबर हैं और दूसरे इस गैदरिंग में 100 हैं तो सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है, जब तक कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हों कि आप एक हैं या 100 हैं। इसलिए कास्ट सेंसस मांगा गया है। आप दे रहे हैं 5-10-15 प्रतिशत... ये सामाजिक न्याय वाली स्कीम्स और वहां आबादी मांग रही है 50 प्रतिशत। इससे क्यों घबरा रही है मोदी सरकार? क्यों सच नहीं जानना? अभी तो कास्ट सेंसस की बात है, सत्य जानने में क्या उनको घबराहट है? उसके बाद हो ना हो... वो बाद की बात है, लेकिन सत्य जानने की कार्रवाई करने से क्यों घबराती है?

इस प्रकार के जैसा मैंने कहा प्रश्न सैकड़ों हैं, लेकिन जिस ऊर्जा से, जिस दिशा से, जिस गति से यह दो दिन मैंने देखा हमारे युवा, हमारे शीर्ष नेतृत्व और राहुल जी कल भी सीडब्ल्यूसी में बोले, अभी बोलने वाले हैं, खरगे जी दोनों बार बोल चुके हैं... इन सबमें जो एक स्फूर्ति, ऊर्जा दिख रही है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस उसको परिवर्तित करेगी सफलता में, राजनीतिक सफलता में। किसी ने कहा कि हम बिल्कुल एमपी-एमएलए बनना चाहते हैं और बनेंगे, लेकिन साथ-साथ आज का जो एक संकट का वातावरण बनाया है इस सरकार ने, उसमें हम सबको गांधी और पटेल और बोस बनने का भी एक अवसर मिलता है और वो अवसर कि हम बोस बनें या पटेल बनें या गांधी बनें, वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम एमपी बनें या एमएलए बनें। तो इन बातों के अलावा शिक्षा नीति पर बात हुई।

यह बताया गया कि जिस प्रकार से जिन स्तंभों की आप बात करते हैं, जिनको कमांडिंग हाइट्स कहा जाता है, जो नींव हैं भारत के आर्थिक सिस्टम की माननीय नेहरू जी ने... जो हमारी जीएनपी है - गांधी-नेहरू-पटेल... उस समय की उपज है। जब-जब ओबीसीज़ के आरक्षण बारे में कानूनी विरोध आया, 50 और 60 के दशक में उच्चतम न्यायालय से आया... तो नेहरू जी ने संविधान का संशोधन किया और अनुच्छेद 15 द्वारा उस आरक्षण को बरकरार किया।

महिलाओं के विषय में... यह नाम कहां से आते हैं... यह बीजेपी से आते हैं? एनी बेसेन्ट, सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी... श्रृंखला लंबी है। यह जो एंपावरमेंट की बात करते हैं हम, यह सिर्फ नाम की बात नहीं करते हैं। हम हर प्रकार से और जो पंचायती राज में एक क्रांति आई है। आज लगभग 15 लाख

और 20 लाख से ज्यादा जो लोग निर्णय लेते हैं पंचायत में सबसे नीचे वाले स्तर पर, वो महिलाएं होती हैं। यह सब कौन लाया है - सब कांग्रेस लाई है।

हमने कहा कि आप सिर्फ अन्नदाता का नाम नहीं लीजिए, कृषक को सिर्फ दुहाई नहीं दीजिए, उसके लिए आप एमएसपी में क्या कर रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 'जय जवान-जय किसान' का स्लोगन दिया था। आज हमने आंकड़े दिए हैं कि जितनी वृद्धि एमएसपी में कांग्रेस के वक्त हुई सभी चीजों में और मुख्य रूप से धान और गेहूं में, लेकिन सभी में... उसका एक फ्रैक्शन भी, उसका एक छोटा हिस्सा भी नहीं आया, उल्टा आपके (मोदी सरकार) के कारण 700 के लगभग अन्नदाताओं को जीवन त्यागना पड़ा... 700! और आप जिद पर अड़े रहे। वो जिद अंततोगत्वा 700 मौतों के बाद, कोलाहल के बाद, ब्लॉकेड के बाद, अस्थिरता के बाद, लगभग 2 वर्ष बाद आपकी ईगो ने यह अनुमति दी आपको कि आप गलती मानें।

मैं अभी आपका समय हर मुद्दे पर नहीं लूंगा। माननीय खरगे जी ने ये भी कहा था, उस पर बहुत तालियां बजीं - कि जो लोग काम नहीं करना चाहते, वो रिटायर हो जाएं। यह नहीं कि अंदर बैठकर एक स्थान आरक्षित रखें और काम भी ना करें। यह भी आप जानते हैं कि हर प्रकार से... एक और बड़ा मुख्य निर्णय है कि जब चयन किया जाएगा, चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है... तो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को निश्चित रूप से उस अधिकार क्षेत्र में लिया जाएगा पूरी तरह से, मीनिंगफुल तरीके से। इसके अलावा जो ढांचे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हैं, उन पर बहुत क्लोज, पैनी दृष्टि से विचार-विमर्श चल रहा है, आप उसका परिणाम देखेंगे। जो कुछ सटीक है, जो कुछ सकारात्मक है, जो कुछ ठोस है, जो संगठन के लिए, जो संघर्ष के लिए, जो संकल्प के लिए मजबूती ज्यादा लाता है, वो सब बदलाव भी आप देखेंगे, मैं सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सभी उन प्रदेशों में जहां अभी अर्जेंसी है।

Sd/-
Secretary
Communication Deptt.
AICC